

[2013] 1 एस.सी.आर 881

गुलाम नबी दार और अन्य

बनाम

जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 6-7/2013)

3 जनवरी, 2013

[अल्तमास कबीर, सीजेआई, सुरिंदर सिंह निजार और जे.चेलामेश्वर, जे.जे.]

जम्मू और कश्मीर राज्य विस्थापित (संपत्ति का प्रशासन) अधिनियम, 2006 - नियम 6 - अधिसूचना के तहत प्रकाशित, अपीलकर्ताओं के कब्जे के तहत भूमि को निष्क्रांत संपत्ति के संरक्षक में निहित घोषित करना - चाहे वह दूषित हो - आयोजित किया गया, हां, क्योंकि अपीलकर्ताओं को यह समझाने का अवसर देने से इनकार कर दिया गया था कि वे केवल संपत्ति के रहने वाले नहीं थे सवाल है, लेकिन उसके किरायेदारों, किस मामले में, 2008 के नियमों के न तो आर 9 और न ही आर 13-सी का मामले के तथ्यों पर कोई आवेदन था - जम्मू और कश्मीर राज्य निकासी (रॉपर्टी का प्रशासन) नियम, 2008- नियम 9 और 13 सी

जम्मू और कश्मीर राज्य विस्थापित (संपत्ति का प्रशासन) अधिनियम, 2006 - नियम. 16 - संरक्षण - जब उपलब्ध हो - अभिनिर्धारित: यह केवल निष्क्रांत संपत्ति के संबंध में इस तरह के प्रभाव

का निर्धारण होने के बाद ही उपलब्ध है - एकतरफा घोषणा स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय और प्रशासनिक निष्पक्षता के सिद्धांतों का विरोध करती है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

जम्मू और कश्मीर राज्य विस्थापित (संपत्ति का प्रशासन) अधिनियम, 2006 - नियम 6 - अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी की गई, जिसमें विचाराधीन भूमि को निष्क्रांत संपत्ति घोषित किया गया - अधिनियम लागू होने से पहले से उक्त भूमि पर अपनी इच्छा से किरायेदार होने का दावा करने वाले कब्जेदारों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रार्थना करते हुए रिट याचिका दायर की कि उक्त अधिसूचना रद्द किया जाए - उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका - पक्षों के बीच न्यायालय के बाहर समझौता हुआ और उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया - विचाराधीन भूमि के कब्जेदारों ने कब्जे में रहते हुए भूमि का कुछ हिस्सा खाली संपत्ति के संरक्षक के पक्ष में आत्मसमर्पण कर दिया था भूमि का शेष भाग, जिसका निपटान उनके साथ किया जाना था - समझौते के अनुसरण में, राज्य के अधिकारियों ने आत्मसमर्पण की गई भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया - लेकिन बाद में उन्होंने यह रुख अपनाया कि आर का अनुपालन न करने के कारण समझौता रद्द हो गया। 13 सी - माना गया: समझौता वैध था और या के उप-नियम (3) के दायरे में था। 23 सीपीसी - मामले के विशेष तथ्य वर्तमान समझौते/निपटान को आर

के संदर्भ में खाली भूमि के पट्टे देने के मामलों से अलग करते हैं। 13 सी - चूंकि जमीनें खाली नहीं थीं, आर का सबसे पहला मानदंड। 13 सी, संतुष्ट नहीं था और भूमि का पट्टा निपटान पैकेट के हिस्से के रूप में दिया जाना था, जिसमें 22 कनाल प्रमुख भूमि का आत्मसमर्पण शामिल था - आर। 13 सी में पार्टियों के बीच हुए समझौते के लिए कोई आवेदन नहीं था और इसलिए, उसके संबंध में दिए जाने वाले पट्टों के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम का निर्धारण करने के लिए भूमि को नीलामी में नहीं रखने के कारण इसे रद्द नहीं किया गया था - यह किसी का मामला नहीं था समझौता किसी धोखाधड़ी का परिणाम था या गैरकानूनी था और उस पर हस्ताक्षर किए जाने और उस पर कार्रवाई किए जाने के बाद, वह पार्टियों के लिए बाध्यकारी था और इसे एकतरफा वापस नहीं लिया जा सकता था - जम्मू और कश्मीर राज्य निकासी (संपत्ति का प्रशासन) नियम, 2008 - नियम 13 सी.

21-11-1980 को, निष्क्रांत संपत्ति के संरक्षक, जम्मू और कश्मीर ने, जम्मू और कश्मीर राज्य निष्क्रांत (संपत्ति का प्रशासन) अधिनियम, 2006 की धारा 6 के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसमें विचाराधीन भूमि को निष्क्रांत संपत्ति घोषित किया गया। उपरोक्त अधिनियम के लागू होने से पहले से ही किरायेदार की हैसियत से उक्त भूमि पर कब्जा होने का दावा करने वाले व्यक्तियों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रार्थना करते हुए रिट

याचिका दायर की कि उक्त अधिसूचना दिनांक 21-11-1980 को रद्द कर दिया जाए। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को मौके पर कोई भी निर्माण करने से रोक दिया। व्यथित होकर इवेक्यू प्रॉपर्टी के कस्टोडियन ने एलपीए दायर किया। जब मामले लंबित थे, अंततः न्यायालय के बाहर पक्षों के बीच समझौता हो गया, जिसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में समझौता दाखिल करने और न्यायालय से उस पर कार्रवाई करने के लिए कहने के बाद, निष्क्रांत संपत्ति के संरक्षक की ओर से इस आधार पर समझौता वापस लेने की अनुमति के लिए एक आवेदन दिया गया था कि मुख्यमंत्री ने 27/28 तारीख को लिए गए पहले के फैसले को उलट दिया था। मार्च, 2005 और, तदनुसार, शपथ पत्र में, अभिसाक्षी, निष्क्रांत संपत्ति के रहने वालों के साथ समझौता करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि ऐसा करने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा वापस ले लिया गया था। राज्य सरकार ने यह रुख अपनाया कि जम्मू और कश्मीर राज्य विस्थापितों (संपत्ति का प्रशासन) नियम, 2008 के नियम 13-सी का अनुपालन न करने के कारण समझौता रद्द हो गया है।

इस बात पर विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या एक समझौते में प्रवेश करने के बाद, जो समाप्त हो गया था और राज्य सरकार द्वारा आत्मसमर्पण

की गई भूमि पर निर्माण करके कार्रवाई की गई थी, क्या राज्य सरकार के कहने पर ही समझौते को एकतरफा वापस लिया जा सकता था।

अपीलकर्ताओं की ओर से की गई दलीलों का मुख्य मुद्दा यह है कि विचाराधीन भूमि निष्क्रांत संपत्ति नहीं है, और अपीलकर्ता अधिनियम लागू होने से पहले से ही किरायेदार थे। वास्तव में, यह कुछ अपीलकर्ताओं का मामला है कि उनके पूर्ववर्तियों ने 1 मार्च, 1947 और 14 अगस्त, 1947 से पहले भी विचाराधीन भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिसने स्पष्ट रूप से अपीलकर्ताओं को संचालन से बाहर कर दिया था। 2006 अधिनियम और 2008 नियमों के प्रावधान। अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि "संरक्षित किरायेदारों" के रूप में, वे भूमि पर कब्जा जारी रखने के हकदार थे और, विशेष रूप से, अपीलकर्ताओं और राज्य अधिकारियों के बीच हुए समझौते के मद्देनजर।

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए-

अभिनिर्धारित किया: 1. जम्मू और कश्मीर राज्य विस्थापित (संपत्ति का प्रशासन) अधिनियम, 2006 की धारा 16 अधिभोग और किरायेदारी अधिकारों से संबंधित है। धारा 16 से यह स्पष्ट है कि गैर-बस्तांटे खंड के कारण, धारा 16 के प्रावधान उस समय लागू किसी भी अन्य कानून पर लागू होंगे और किसी निष्क्रमित व्यक्ति की किसी भी भूमि पर कब्जे का अधिकार समाप्त नहीं होगा। तदनुसार, यदि किरायेदार अपने कब्जे वाली

भूमि के संबंध में अधिभोग अधिकारों का आनंद ले रहे थे, तो उन्हें 2006 अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर वहां से बेदखल नहीं किया जा सकता था। हालाँकि, धारा 16 के तहत सुरक्षा केवल निष्क्रांत संपत्ति के संबंध में ऐसे प्रभाव का निर्धारण होने के बाद ही उपलब्ध होगी। एकतरफ़ा घोषणा स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय और प्रशासनिक निष्पक्षता के सिद्धांतों के विपरीत है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। [पैरा 32) [899-सी, एफ-एच; 900-ए]

2. 2006 अधिनियम की धारा 6 के तहत 21 नवंबर, 1980 को प्रकाशित अधिसूचना, जिसमें अपीलकर्ताओं के कब्जे वाली भूमि को निष्क्रांत संपत्ति के संरक्षक में निहित करने की घोषणा की गई थी, अप्रचलित हो गई, क्योंकि अपीलकर्ताओं को अवसर से वंचित कर दिया गया था। यह समझाते हुए कि वे केवल विचाराधीन संपत्ति के रहने वाले नहीं थे, बल्कि उसके किरायेदार थे, इस मामले में, न तो नियम 9 के प्रावधान और न ही 2008 के नियमों के नियम 13-सी का इस मामले के तथ्यों पर कोई आवेदन होगा। [पैरा 34] [900-सी-डी]

3. उपरोक्त के अलावा, किया गया समझौता कई कारकों पर निर्भर था, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि विचाराधीन भूमि के रहने वालों ने शेष रहते हुए 37 कनाल और 5 मरला में से 22 कनाल प्रमुख भूमि कस्टोडियन विभाग के पक्ष में आत्मसमर्पण कर दी थी। 15 कनाल और 5

मरले पर कब्जा था, जिसका निपटान उनके साथ किया जाना था। जहां एक ओर, राज्य के अधिकारियों ने इसका फायदा उठाया। समर्पण की गई जमीनों पर बंदोबस्त और निर्माण किए गए, बाद में राज्य सरकार की ओर से यह रुख अपनाया गया कि समझौता रद्द हो गया है। 2008 के नियमों के नियम 13-सी के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण। इस मामले की तथ्यात्मक स्थिति नीचे दी गई परिस्थितियों से भिन्न है। 2008 नियमावली का नियम 13 सी. वर्तमान मामले में, निपटान के अंतर्गत आने वाली भूमि खाली नहीं थी और इसलिए, जब निपटान प्रारंभिक चरण में था, तब नियम 13-सी के दायरे में नहीं थी। यह केवल समझौते के तहत है कि रिट याचिकाकर्ताओं के दावे और अधिकार, यदि कोई हों, को आत्मसमर्पण करना आवश्यक था और इसलिए, 37 कनाल और 5 मरला में से 22 कनाल भूमि के कब्जे के वास्तविक आत्मसमर्पण का सवाल था। पालन करें, इसके संबंध में अधिभोग अधिकारों और किरायेदारों को आवंटित करने के लिए शेष 15 कनाल और 5 मरला छोड़ दें। [पैरा 35] [900-ई-एच; 901-ए-बी]

4. मामले के विशेष तथ्य वर्तमान समझौते को नियम 13-सी के संदर्भ में रिक्त भूमि के पट्टे देने के मामलों से अलग करते हैं और इसलिए, इसे अलग तरीके से माना जाना चाहिए। सबसे पहले, चूंकि भूमि खाली नहीं थी, नियम 13-सी का पहला मानदंड पूरा नहीं हुआ था और

भूमि का पट्टा निपटान पैकेट के हिस्से के रूप में दिया जाना था, जिसमें 22 कनाल प्रमुख भूमि का समर्पण शामिल था। इस मामले के विशेष तथ्यों में, 2008 के नियमों के नियम 13-सी का पार्टियों के बीच हुए समझौते पर कोई लागू नहीं होगा और इसलिए, यह निर्धारित करने के लिए भूमि को नीलामी में नहीं रखने के कारण इसे रद्द नहीं किया जाएगा। उसके संबंध में दिए जाने वाले पट्टों के लिए भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम। यह किसी का मामला नहीं था कि समझौता किसी धोखाधड़ी का परिणाम था या गैरकानूनी था और उस पर हस्ताक्षर किए जाने और कार्रवाई किए जाने के बाद, पार्टियों के लिए बाध्यकारी था और इसे एकतरफा वापस नहीं लिया जा सकता था। [पैरा 36] [901-8-ई]

5. समझौता पार्टियों के बीच हुआ और स्वीकृति के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया, यह वैध है और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 के उप-नियम (3) के दायरे में है। यह नहीं माना जा सकता कि समझौता 2008 के नियमों के नियम 13-सी के प्रावधानों के विपरीत था: उच्च न्यायालय न्यायालय के बाहर निपटान की स्वीकृति और अधिकारों के समायोजन के लिए उचित आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा। उसके संदर्भ में पार्टियों की। [पैरा 37] [901-एफ-जी, एच; 902-ए]

सिविल अपील की क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6-7/2013

श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय द्वारा एलपीए संख्या 169/2004 में सीएमपी संख्या 128/2006 और 525/ 2004 में निर्णय और आदेश दिनांक 25.03.2008 से उत्पन्न।

साथ में

सी.ए. संख्या 8-9/2013

भास्कर गुप्ता, जफर अहमद शाह, पूर्णिमा भट, अपीलार्थियों की ओर से।

सुनील फर्नांडीस, वेमिका तमर, आस्था शर्मा, इंशा मीर, प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया इनके द्वारा दिया गया-

अलतमस कबीर, मुख्य न्यायाधिपति. 1. अवकाश स्वीकृत।

2. पार्टियों के बीच विवाद 37 कनाल 5 मरला भूमि से संबंधित हैं, जो 2003 के ओडब्ल्यूपी नंबर 480 और 2005 के ओडब्ल्यूपी नंबर 454 की विषय वस्तु बनाने वाले कई सर्वेक्षण नंबरों में शामिल हैं। 21 नवंबर, 1980 को इवैक्यू संपत्ति के संरक्षक , कश्मीर ने जम्मू और कश्मीर राज्य विस्थापित (संपत्ति का प्रशासन) अधिनियम, 2006 की धारा 6 के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसे इसके बाद "2006 अधिनियम" के रूप में

जाना जाएगा, उपरोक्त भूमि को एक के स्वामित्व में होने के कारण निष्क्रांत संपत्ति घोषित किया गया। क्रमर-उद-दीन और अन्य निकासी। चूँकि, 2003 के ओडब्ल्यूपी संख्या 480 में रिट याचिकाकर्ताओं ने, रिट याचिका में शामिल भूमि के किरायेदारों की इच्छा का दावा करते हुए, मिट्टी भरना शुरू कर दिया था, उन्हें निकासी विभाग द्वारा ऐसा करने से रोक दिया गया था। यह रिट याचिकाकर्ताओं का मामला है कि जब उन्होंने पूछताछ की, तो वे रिकॉर्ड पर हाथ रखने में सक्षम थे, जिससे संकेत मिलता है कि उक्त सर्वेक्षण संख्या में शामिल भूमि में से 11 कनाल 6 मरला भूमि को निकासी विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया था। और 22 जनवरी, 2003 और 1 फरवरी, 2003 को तीन जब्ती ज्ञापनों के माध्यम से कस्टोडियन के सुपरडनामे में रखा गया। यह दावा करते हुए कि वे उपरोक्त अधिनियम के लागू होने से पहले से किरायेदारों की क्षमता में भूमि पर कब्जा कर रहे थे। 2003 के ओडब्ल्यूपी संख्या 480 में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की:-

"(i) यह घोषित किया जाए कि जम्मू-कश्मीर निष्क्रमण (संपत्ति का प्रशासन) अधिनियम, 2006 की धारा 6 असंवैधानिक है;

(ii) यह घोषित किया जाए कि कृषि सुधार अधिनियम, 1976 की धारा 3, जहां तक यह निष्क्रांत भूमि के

किरायेदारों पर धारा 4 और 8 के आवेदन को बाहर करती है, संविधान के दायरे से बाहर है।

(iii) उचित रिट, निर्देश या आदेश द्वारा, जिसमें सर्टिओरी प्रकृति की रिट भी शामिल है, निम्नलिखित अधिसूचना/संचार को रद्द कर दिया जाए:-

1. अधिसूचना दिनांक 21.11.1980
2. संचार क्रमांक CEPS/GE/2002/2766-70 दिनांक 17.12.2002.
3. संचार क्रमांक सीजी(ईपी)1020/2003/167-विविध। के दिनांक 23.1.2003
4. तीन जब्ती ज्ञापन दिनांक 2.2.2003
5. संचार संख्या सीईपीई-जेई/2002/3347-50 दिनांक 6.2.2003
6. संचार क्रमांक डीएफएल/एसजी/378 दिनांक 22.2.2003

(iv) उचित रिट, निर्देश या आदेश द्वारा, जिसमें निषेध की प्रकृति की रिट भी शामिल है, उत्तरदाताओं को भूमि में याचिकाकर्ताओं के कब्जे के अधिकारों और उनकी भूमि को

समतल करने और बाड़ लगाने से हस्तक्षेप करने से रोका जा सकता है।

(v)"

रिट याचिका के साथ, याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहत की मांग करते हुए एक विविध याचिका भी दायर की जिसमें यह आदेश दिया गया कि प्रतिवादियों को अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं को विवाद वाली भूमि से बेदखल नहीं करना है। याचिकाकर्ताओं को उक्त अवधि के दौरान कोई भी निर्माण करने या उक्त भूमि की प्रकृति और चरित्र को बदलने से भी रोक दिया गया था। हालाँकि, जब रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, कस्टोडियन ने निषेधाज्ञा के उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू किया, तो याचिकाकर्ताओं ने एक और सीएमपी दायर किया जिसमें 22 अप्रैल, 2004 को नोटिस जारी किया गया था, जिसे चार सप्ताह के भीतर वापस किया जाना था। और तब तक पार्टियों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया। इसके बाद, 30 सितंबर, 2004 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को दौरा करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, जो उन्होंने 7 अक्टूबर, 2004 को किया था।

3. रिपोर्ट प्राप्त होने पर और इस बात से संतुष्ट होने पर कि कस्टोडियन द्वारा उपरोक्त भूमि पर निर्माण कार्य किया गया था और आगे

बढ़ाया जा रहा था, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19 नवंबर, 2004 द्वारा प्रतिवादियों को कोई भी निर्माण करने से रोक दिया। स्थान। चूँकि कस्टोडियन द्वारा इसके पहले के आदेशों का उल्लंघन किया गया था, इसलिए संबंधित पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी को यह देखने के लिए निर्देशित किया गया था कि याचिका पर विचार किए जाने तक, या अगले आदेश तक, न्यायालय के आदेश का विधिवत अनुपालन किया जाए।

4. विद्वान सिविल न्यायाधीश के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, निष्क्रांत संपत्ति के संरक्षक ने एलपीए संख्या 169/2004 दायर की। अन्य रिट याचिकाकर्ताओं ने भी किरायेदार के रूप में और "संरक्षित" के रूप में अपनी भूमि पर कब्जा करने का दावा किया। किरायेदारों" ने जम्मू और कश्मीर इवेक्यू (संपत्ति का प्रशासन) अधिनियम, 2006 की धारा 6 और कृषि सुधार अधिनियम, 1976 की धारा 3 के प्रावधानों की वैधता को भी चुनौती दी है, क्योंकि इसमें धारा 4 और 8 के आवेदन को शामिल नहीं किया गया है। निष्क्रांत संपत्तियों के किरायेदारों को बांधने के लिए।

5. जब मामले लंबित थे, तो पक्षों द्वारा न्यायालय के बाहर समाधान के लिए गंभीर प्रयास किए गए, जो अंततः समझौते के रूप में फलीभूत हुआ, जिसे 2006 के सीएमपी संख्या 128 के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। समझौता न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया

गया। कोर्ट पर इवेक्यू प्रॉपर्टी के कस्टोडियन, कश्मीर और सभी रिट याचिकाकर्ताओं और उनके वकील द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे। जब उपरोक्त विविध याचिका विचाराधीन थी, तब महाधिवक्ता ने 23 मई, 2006 को एक आवेदन दायर कर समझौता स्वीकार न करने की प्रार्थना की, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। इसी बीच सरकार बदल गई और कस्टोडियन का भी तबादला हो गया। नए कस्टोडियन ने मामले को वापस राज्य सरकार को सौंपने का निर्णय लिया। 10 अक्टूबर, 2006 को, कस्टोडियन ने सीएमपी नंबर 128/2006 में निहित निपटान को वापस लेने की प्रार्थना करते हुए एक आवेदन दायर किया, और इस तरह के आवेदन के समर्थन में, कस्टोडियन ने राजस्व विभाग के एक पत्र पर भरोसा किया जिसमें यह कहा गया था कि राजस्व मंत्री ने निष्क्रांत संपत्ति के कब्जेदारों के साथ समझौता करने के लिए 27/28 मार्च, 2005 को लिए गए पूर्व निर्णय को उलटने की मंजूरी दे दी थी। कस्टोडियन द्वारा दायर निपटान को वापस लेने के लिए उक्त आवेदन को 2006 के सीएमपी नंबर 525 के रूप में पंजीकृत किया गया।

6. समझौते के संदर्भ में अपील और रिट याचिकाओं के निपटारे के लिए पार्टियों द्वारा दायर की गई दो विविध याचिकाएं, सीएमपी संख्या 128/2006 और निपटान को वापस लेने के लिए कस्टोडियन द्वारा दायर की गई सीएमपी संख्या 525/2006 हैं। 15 सितंबर, 2007 को माननीय

श्री न्यायमूर्ति एच. लम्तियाज हुसैन और माननीय श्री न्यायमूर्ति मंसूर अहमद मीर की खंडपीठ के समक्ष विचार के लिए आया। जैसा कि यहां पहले संकेत दिया गया है, माननीय न्यायाधीशों में मतभेद था। राहत की प्रार्थना की। जबकि एच. लम्तियाज हुसैन, जे. ने माना कि निपटान ने जम्मू और कश्मीर राज्य विस्थापितों (संपत्ति का प्रशासन) नियम, 2008 के नियम 13-सी का उल्लंघन किया है, जिसे इसके बाद "2008 के नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है और इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाए, मंसूर अहमद मीर जे ने माना कि उपरोक्त नियम मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है और यह किसी का मामला नहीं है, जो समझौता हुआ वह धोखाधड़ी या गैरकानूनी का परिणाम था। उनके आधिपत्य का यह भी विचार था कि समझौते पर पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए और कार्रवाई की गई, यह पार्टियों के लिए बाध्यकारी था और इसे एकतरफा वापस नहीं लिया जा सकता था। इसलिए, हिज लॉर्डशिप ने निपटान को वापस लेने के लिए कस्टोडियन द्वारा दायर सीएमपी नंबर 525/2006 को खारिज कर दिया और आगे की दलीलों के लिए एलपीए नंबर 169/2004 और सीएमपी नंबर 128/2006 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। इस तरह के मतभेदों को देखते हुए, मामले को तीसरे न्यायाधीश के पास भेजने के लिए, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय नियमों के नियम 36(2) के संदर्भ में मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया था।

विद्वान तृतीय न्यायाधीश ने विचारार्थ तीन प्रश्न बनाये, अर्थात्

(ए) क्या 2008 के नियमों का नियम 13-सी पार्टियों द्वारा किए गए समझौते पर लागू होता है?

(बी) क्या समझौता नियम 13 का उल्लंघन करता है?

(सी) क्या कस्टोडियन एकतरफा निपटान से हट सकता है?

7. विद्वान तीसरे न्यायाधीश के समक्ष राज्य की ओर से यह आग्रह किया गया कि विचाराधीन भूमि का हिस्सा कमर-उद-दीन का है, जिसके दो भाई थे, अहमद दीन और इमाम दीन। 1947 की गड़बड़ी में कमर-उद-दीन राज्य छोड़कर विस्थापित हो गए और उनकी संपत्ति को निष्क्रांत संपत्ति घोषित कर दिया गया। 1949 या 1950 में कस्टोडियन विभाग में ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। इसके बाद, अहमद दीन ने 11 वीं असुज 2009 को निष्क्रांत संपत्तियों के संरक्षक के समक्ष तीन आवेदन प्रस्तुत किए, जिसमें अनुरोध किया गया कि परिसर सहित तीन बंगलों को गैर-निष्क्रिय संपत्ति घोषित किया जाए क्योंकि पूरी संपत्ति तीन भाइयों, कमर-उद- के पास थी। दीन, अहमद दीन और इमाम दीन। उक्त तीन आवेदन 28 जुलाई, 1956 को डिफॉल्ट के आधार पर खारिज कर दिए गए थे। उक्त आदेश की समीक्षा के लिए एक आवेदन 20 नवंबर, 1956 को दायर किया गया था, जिसे कस्टोडियन ने अपने आदेश दिनांक 5 सितंबर, 1963 द्वारा

निपटा दिया था, जिससे विस्थापितों के करीबी रिश्तेदारों को संपत्तियों के प्रबंधकों के रूप में नियुक्त किया गया था, बशर्ते कि उन्होंने यह वचन दिया हो कि वे आय और व्यय का वार्षिक लेखा-जोखा विभाग को प्रस्तुत करेंगे और संपत्तियों से होने वाली आय को नियमित रूप से जमा करेंगे ताकि उसे उनके नाम के सामने जमा किया जा सके। निकासी इसलिए, राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि उपरोक्त आदेशों के अनुसार, संपत्ति निकासी विभाग के नियंत्रण में आती है और इसके आवंटियों और इसके द्वारा नियुक्त प्रबंधकों के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। राज्य का यह भी रुख था कि एक बार जब कस्टोडियन निष्क्रांत संपत्तियों के नियंत्रण में आ गया, तो उसने जमीन पर एक शॉपिंग मॉल बनाने का फैसला किया और निर्माण का काम एक ठेकेदार को आवंटित कर दिया, जिसने उसके बाद निर्माण शुरू कर दिया। यह भी आग्रह किया गया था कि रिट याचिकाकर्ताओं के किरायेदार के रूप में भूमि पर कब्जे के दावे के बावजूद, भूमि में उनके अधिकार, यदि कोई हों, निष्क्रांत संपत्ति अधिनियम लागू होने के बाद समाप्त हो गए थे और किसी भी मामले में इसके आधार पर 2006 अधिनियम की धारा 6 के तहत जारी घोषणा।

8. राज्य का यह भी मामला था कि 2008 के नियमों के नियम 13-सी के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना राज्य की भूमि के किसी भी आवंटन का निपटान नहीं किया जा सकता था और इस तरह के उल्लंघन

ने निपटान को अमान्य कर दिया, जो इसलिए अवैध था। और एच. लम्तियाज़ हुसैन, जे. द्वारा इसे उचित रूप से घोषित किया गया था। दूसरी ओर, रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री शाह द्वारा यह तर्क दिया गया कि पार्टियों के बीच समझौता एक अनुबंध की प्रकृति में था और उन पार्टियों द्वारा किया गया था जिन्होंने अनुबंध करने की स्वतंत्रता का आनंद लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवंटित की जाने वाली भूमि खाली होती तो नियम 13-सी लागू हो सकता था। श्री शाह के अनुसार, चूंकि याचिकाकर्ताओं के पास किरायेदार के रूप में जमीन थी, इसलिए यह नियमों के नियम 13-सी के प्रयोजनों के लिए खाली नहीं थी। श्री शाह के अनुसार, माननीय न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर द्वारा व्यक्त किए गए विचार नियम 13-सी के अनुरूप थे, जो मामले के तथ्यों के अनुसार, विचाराधीन भूमि पर कोई लागू नहीं हो सकता था।

9. श्री शाह द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि यह मानते हुए भी कि नियम 13-सी लागू था, तब भी इसके प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि वर्तमान मामले में प्रीमियम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तय किया गया था कि रिट याचिकाकर्ता थे संपूर्ण भूमि के संबंध में अपने सभी अधिकारों का समर्पण करना। प्रीमियम का निर्धारण कस्टोडियन विभाग के प्रभारी मंत्री के अलावा किसी और की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्यों द्वारा किया गया था। श्री शाह ने विद्वान तृतीय न्यायाधीश के समक्ष यह भी

प्रस्तुत किया कि 30 लाख रुपये प्रति कनाल की दर, जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा इंगित किया गया था, किसी भी प्रासंगिक सामग्री पर आधारित नहीं थी।

10. जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, इस मामले में विवाद विचाराधीन भूमि के संबंध में नियम 13-सी की प्रयोज्यता से संबंधित है। 25 मार्च, 2008 को अपने फैसले और आदेश में, विद्वान तृतीय न्यायाधीश, वाई.पी. नरगोत्रा। जे. एच. लम्तियाज़ हुसैन, जे. द्वारा अपनाए गए विचार से सहमत थे कि पार्टियों ने उपर्युक्त नियमों के नियम 13-सी का उल्लंघन किया है और इसलिए, कस्टोडियन इसे एकतरफा वापस लेने के लिए सक्षम है। विद्वान न्यायाधीश इस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समझौते के अनुसार, रिट याचिकाकर्ताओं को पूरी भूमि पर अपने सभी अधिकार छोड़ने होंगे, जिससे नियम 13-सी के अर्थ के तहत भूमि खाली हो जाएगी।

11. इस सवाल पर कि क्या समझौते ने नियम 13-सी का उल्लंघन किया है, विद्वान तीसरे न्यायाधीश का विचार था कि समझौते के तहत उत्तरदाताओं/रिट याचिकाकर्ताओं को दिए जाने वाले पट्टे के लिए भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम निर्धारित नहीं किया गया था। पट्टे को खुली नीलामी में रखना नियम 13-सी की अनिवार्य आवश्यकता का उल्लंघन था। इसलिए, विद्वान न्यायाधीश ने माना कि निपटान ने देय प्रीमियम के निर्धारण के बिंदु पर नियम 13-सी का उल्लंघन किया है।

12. तीसरे प्रश्न पर कि क्या कस्टोडियन एकतरफा निपटान से हट सकता है, विद्वान तीसरे न्यायाधीश ने कहा कि आदेश 23 सीपीसी का नियम 3, जो मुकदमों के समझौते से संबंधित है, लागू होगा बशर्ते कि यह संतुष्टि के लिए साबित हो। न्यायालय ने कहा कि मुकदमा किसी कानूनी समझौते या समझौते द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से समायोजित कर दिया गया है। ऐसे मामले में, न्यायालय के पास इस तरह के समझौते या समझौते को दर्ज करने का आदेश देने का विवेकाधिकार होगा और जहां तक यह मुकदमे के पक्षों से संबंधित है, उसके अनुसार एक डिक्री पारित करेगा। विद्वान तीसरे न्यायाधीश ने आदेश 23 सीपीसी के नियम 3 के स्पष्टीकरण पर ध्यान दिया, जो यह प्रावधान करता है कि एक समझौता या समझौता जो अनुबंध अधिनियम के तहत शून्य या शून्यकरणीय है, उसे नियम के अर्थ में वैध नहीं माना जाएगा। तदनुसार, उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार, एक समझौता जो वैध नहीं पाया गया, उसे डिक्री पारित करने के उद्देश्य से न्यायालय द्वारा खारिज किया जा सकता है। विद्वान तीसरे न्यायाधीश ने तब अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 का उल्लेख किया, जिसके तहत कोई भी समझौता जिसे न्यायालय अनैतिक या सार्वजनिक नीति के विपरीत मानता है, शून्य है। विद्वान तीसरे न्यायाधीश ने माना कि समझौता अनुबंध अधिनियम की धारा 23 से सीधे तौर पर प्रभावित हुआ क्योंकि इसने नियम 13-सी के उद्देश्य को विफल कर दिया और इसलिए, आदेश 23 सीपीसी के नियम 3 के प्रयोजनों के

लिए गैरकानूनी था। विद्वान तृतीय न्यायाधीश ने माना कि निपटान गैरकानूनी है, संरक्षक एकतरफा निपटान से हटने का हकदार था। एच. लम्तियाज़ हुसैन, जे. द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत होते हुए, विद्वान तीसरे न्यायाधीश ने कहा कि सहमति या समझौते से, पार्टियां वह हासिल नहीं कर सकतीं जो कानून के विपरीत है और पार्टियों के बीच हुआ समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

13. उपरोक्त के परिणामस्वरूप, जबकि दो विविध याचिकाओं का उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा कर दिया गया था, 21 नवंबर, 1980 की अधिसूचना को चुनौती देने वाले अपीलकर्ताओं द्वारा दायर एलपीए संख्या 169/2004 और ओडब्लूपी संख्या 480/2003, हैं। अभी भी हाई कोर्ट में फैसला लंबित है।

14. ये दोनों अपीलें उक्त विविध आवेदनों में श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के विद्वान तीसरे न्यायाधीश द्वारा पारित 25 मार्च, 2008 के अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई हैं।

15. संक्षेप में कहा गया है, अपीलकर्ताओं की शिकायत एच. लम्तियाज़ हुसैन, जे. द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें कहा गया है कि निपटान ने 2008 के नियमों के नियम 13-सी का उल्लंघन किया है और इसलिए, इसे न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

16. अपीलकर्ताओं के लिए अपील करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री ज़फ़र अहमद शाह ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ दोहराईं और प्रस्तुत किया कि, हालांकि, निकासी विभाग ने 21 नवंबर, 1980 को अधिसूचना जारी की थी, लेकिन इसे न तो राजपत्रित किया गया और न ही लागू किया गया। 1999 तक, जब उस संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में एक प्रविष्टि की गई थी। श्री शाह ने आग्रह किया कि सभी अपीलकर्ता उस भूमि के संबंध में किरायेदार थे, जिस पर उनका कब्जा था और ऐसा कब्जा 2006 अधिनियम की धारा 16 के तहत संरक्षित था। कस्टोडियन जनरल का आक्षेपित आदेश, उक्त प्रावधानों के विपरीत होने के कारण, अवैध था और रद्द किये जाने योग्य था।

17. श्री शाह ने तर्क दिया कि विचाराधीन भूमि और आसपास के क्षेत्रों में शामिल भूमि कृषि भूमि थी और दशकों से धान की खेती के लिए उपयोग की जाती थी। जब एक बाईपास सड़क और एक नए हवाई अड्डे का निर्माण किया गया, तो आसपास की भूमि के उपयोग में बदलाव आया। इस तरह के विकास और शहर के विस्तार के परिणामस्वरूप, हैदर पोरा नामक क्षेत्र में और उसके आसपास बड़ी संख्या में आवासीय घर और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बनाए गए। इस तरह की अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों के कारण, मिट्टी भरने के कारण निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली भूमि का स्तर काफी बढ़ गया था। दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं

की भूमि नीची बनी रही और धीरे-धीरे पानी का पात्र बन गई, जिससे वे खेती के लिए अनुपयुक्त हो गईं। भूमि को उपयोग योग्य बनाने के लिए, अपीलकर्ताओं ने पानी के संग्रह और ठहराव को रोकने के लिए मिट्टी भरने का भी सहारा लिया। इस स्तर पर, निकासी विभाग के पदाधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और अपीलकर्ताओं को संबंधित भूमि में मिट्टी भरने का काम जारी रखने से रोक दिया।

18. श्री शाह ने प्रस्तुत किया कि कस्टोडियन जनरल के कार्यालय द्वारा कथित एकतरफा पूछताछ के बाद, इवेक्यू संपत्ति के कस्टोडियन को पत्र जारी किए गए थे, जिसमें उन्हें अपीलकर्ताओं के कब्जे वाली भूमि पर कब्जा फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, अपीलकर्ताओं को इस तरह की जांच के संबंध में पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया था और अपीलकर्ताओं के पीछे भूमि की स्थिति के बारे में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कस्टोडियन जनरल के कार्यालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कानूनी मंजूरी के बिना थी और रद्द किये जाने योग्य थी।

19. श्री शाह ने आग्रह किया कि अपीलकर्ता और उनके पूर्ववर्तियों ने 14 अगस्त, 1947 से बहुत पहले किरायेदार के रूप में अपनी क्षमता में भूमि पर कब्जा कर रखा था और इसलिए, किसी भी कार्रवाई के खिलाफ कानून द्वारा संरक्षित हैं। उत्तरदाताओं. श्री शाह ने आग्रह किया कि, हालांकि, उत्तरदाताओं ने दावा किया कि विचाराधीन संपत्ति किसी क्रमर-उद-दीन की

है, लेकिन 1 मार्च, 1947 या 14 अगस्त, 1947 और उसके पूर्ववर्तियों के अनुसार वह कभी भी भूमि के कब्जे में नहीं था। -अपीलकर्ताओं के हित में किरायेदार के रूप में संपत्ति पर कब्जा था और, किसी भी स्तर पर, उन्होंने उक्त संपत्ति पर कब्जा करना बंद नहीं किया।

20. श्री शाह ने आग्रह किया कि 2006 अधिनियम की धारा 5 के तहत, राज्य में स्थित सभी निष्क्रांत संपत्ति को कस्टोडियन में निहित माना जाएगा। हालाँकि, कस्टोडियन में निहित होने के लिए, संपत्तियों को निष्क्रांत संपत्ति होना चाहिए। श्री शाह ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, कमर-उद-दीन उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 (सी) के अर्थ के तहत विस्थापित नहीं था, न ही उसने धारा 2 (सी) में बताए गए तरीके से संपत्ति अर्जित की थी। iii) तत्संबंधी। श्री शाह ने प्रस्तुत किया कि संपत्ति को 2006 अधिनियम की धारा 5 के अनुसार कस्टोडियन द्वारा निष्क्रांत संपत्ति के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है।

21. विद्वान वकील ने तब प्रस्तुत किया कि 2006 अधिनियम की धारा 6 असंवैधानिक थी और रद्द किये जाने योग्य थी। यह आग्रह किया गया कि 2006 अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले, यह सुनिश्चित करना अधिकारियों पर निर्भर था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाए।

22. श्री शाह ने तर्क दिया कि 2008 के नियमों में प्रावधान है कि किसी भी निष्क्रांत संपत्ति के संबंध में जो कस्टोडियन में निहित है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, जिसके पास ऐसे कब्जे का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, कस्टोडियन उस व्यक्ति को ऐसी संपत्ति से बेदखल कर सकता है। 2006 अधिनियम और 2008 नियमों में बताए गए तरीके से।

23. श्री भास्कर गुप्ता, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो अपीलकर्ताओं, गुलाम मोहम्मद डार और अन्य की ओर से उपस्थित हुए, ने 2008 के नियमों के नियम 13-सी में "रिक्त" अभिव्यक्ति के उपयोग पर जोर दिया। श्री गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि "रिक्त" शब्द को ब्लैक लॉ डिक्शनरी में "खाली, खाली, बिल्कुल स्वतंत्र और लावारिस" के रूप में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, अधिनियम और नियमों के लागू होने से पहले किसी भी व्यक्ति के कब्जे में मौजूद भूमि को खाली भूमि नहीं कहा जा सकता है और, तदनुसार, 2008 के नियमों के नियम 13-सी का विचाराधीन भूमि पर कोई लागू नहीं होगा। सभी।

24. श्री गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं और राज्य एजेंसियों के बीच हुए समझौते के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने कस्टोडियन विभाग के पक्ष में 37 कनाल और 5 मरला में से 22 कनाल प्रमुख भूमि का कब्जा सौंप दिया था और शेष भूमि पर अपीलकर्ताओं का कब्जा जारी रहा। इसके अलावा, श्री गुप्ता के अनुसार, समर्पित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने से,

निपटान पर विधिवत कार्रवाई की गई थी और इसलिए, अब राज्य इससे पीछे नहीं हट सकता। राज्य के लिए यह तर्क देना अब खुला नहीं था कि वे गलत तरीके से समझौते पर पहुंचे थे। श्री गुप्ता ने यह भी बताया कि यह तथ्य कि अपीलकर्ताओं का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा था और रहेगा, यह राज्य सरकार, उसके राजस्व विभाग की ओर से कस्टोडियन जनरल को लिखे गए एक पत्र से भी स्पष्ट होगा। 2004 के एलपीए नंबर 169 और 2003 के ओडब्ल्यूपी नंबर 480 में दायर किए जाने वाले निपटान के संबंध में 10 अक्टूबर, 2006 को। यह बताया गया था कि, उक्त पत्र में, राज्य सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि अपीलकर्ता कब्जेदार थे। विचाराधीन संपत्ति का, भले ही इस तरह के कब्जे को अवैध बताया गया था। श्री गुप्ता ने कहा कि जो महत्वपूर्ण है वह इस तथ्य को स्वीकार करना है कि अपीलकर्ताओं के पास विचाराधीन भूमि का वास्तविक कब्जा था।

25. अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि आदेश 23 सीपीसी का नियम 3 मुकदमों के समझौते की अनुमति देता है और जहां यह न्यायालय की संतुष्टि के लिए साबित हो गया है कि इसे किसी भी कानूनी समझौते या लिखित रूप में समझौते द्वारा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से समायोजित किया गया था और हस्ताक्षरित किया गया था। पक्षों,

न्यायालय ऐसे समझौते, समझौते या संतुष्टि को दर्ज करने का आदेश देगा और फिर डिक्री पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा।

26. विद्वान वकील श्री सुनील फर्नांडीस, जो जम्मू और कश्मीर राज्य की ओर से पेश हुए, ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन भूमि पर कब्जा फिर से शुरू करने के संबंध में दो रिट याचिकाएँ अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थीं और धारा 6 की वैधता 2006 का अधिनियम उसमें चुनौती का विषय था। उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षों के बीच विवाद का दायरा 2006 अधिनियम की धारा 6 की वैधता के प्रश्न तक ही सीमित था, साथ ही पक्षों के बीच हुए समझौते को चुनौती भी थी।

27. श्री फर्नांडीस ने आग्रह किया कि विद्वान तीसरे न्यायाधीश का दृष्टिकोण मामले में बहुमत के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः ये अपीलें खारिज किये जाने योग्य थीं।

28. अपीलकर्ताओं की ओर से की गई दलीलों का मुख्य मुद्दा यह है कि विचाराधीन भूमि निष्क्रांत संपत्ति नहीं है, और अपीलकर्ता अधिनियम लागू होने से पहले से ही किरायेदार थे। वास्तव में, यह कुछ अपीलकर्ताओं का मामला है कि उनके पूर्ववर्तियों ने 1 मार्च, 1947 और 14 अगस्त, 1947 से पहले भी विचाराधीन भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिसने स्पष्ट रूप से अपीलकर्ताओं को संचालन से बाहर कर दिया था। 2006 अधिनियम

और 2008 नियमों के प्रावधान। दूसरी ओर, "संरक्षित किरायेदारों" के रूप में, अपीलकर्ता भूमि पर कब्जा जारी रखने के हकदार थे और, विशेष रूप से, अपीलकर्ताओं और राज्य अधिकारियों के बीच हुए समझौते के मद्देनजर।

29. यह कि, पार्टियों के बीच कोई समझौता हुआ था, यह मुद्दा नहीं है। यह भी मुद्दा नहीं है कि न्यायालय में समझौता दाखिल करने और न्यायालय से उस पर कार्रवाई करने के लिए कहने के बाद, निष्क्रांत संपत्ति के संरक्षक, जम्मू और कश्मीर की ओर से 2006 के सीएमपी नंबर 128 को वापस लेने की अनुमति के लिए एक आवेदन किया गया था। आधार यह है कि मुख्यमंत्री ने 27/28 मार्च, 2005 को लिए गए पहले के फैसले को उलट दिया था और, तदनुसार, शपथ पत्र में अभिसाक्षी, समझौते में शामिल होने के लिए सक्षम नहीं था, क्योंकि ऐसा करने का निर्णय वापस ले लिया गया था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा।

30. निर्णय लेने का प्रश्न यह है कि क्या एक निपटान में प्रवेश करने के बाद, जिसे खारिज कर दिया गया था और राज्य सरकार द्वारा आत्मसमर्पण की गई भूमि पर निर्माण करके कार्रवाई की गई थी, क्या निपटान को केवल राज्य सरकार के कहने पर एकतरफा वापस लिया जा सकता था ?

31. अपीलकर्ताओं की ओर से की गई दलीलों की दूसरी शाखा, जो विचार करने योग्य है, वह यह है कि क्या 2006 के अधिनियम की धारा 8 को अधिकारातीत घोषित किए जाने पर, किसी पक्ष को इसके तहत जारी अधिसूचना को चुनौती देने के अधिकार के रूप में किसी उपाय के बिना छोड़ा जा सकता है। ऐसी घोषणा से धारा 6 समाप्त हो गई?

32. उपरोक्त के अतिरिक्त, 2006 अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। धारा 16, जो अधिभोग और किरायेदारी अधिकारों से संबंधित है, इस प्रकार प्रदान करती है:-

“16. अधिभोग या किरायेदारी का अधिकार 0 न होना समाप्त - तत्समय लागू किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, किसी विस्थापित की किसी भी भूमि पर अधिभोग का अधिकार, जो अभिरक्षक में निहित है, समाप्त नहीं होगा, न ही कोई निष्क्रमणकर्ता या अभिरक्षक, चाहे वह अधिभोगी किरायेदार के रूप में हो, समाप्त नहीं होगा। , या किसी भी भूमि पर एक निश्चित अवधि के लिए किरायेदार, कस्टोडियन के किसी भी डिफॉल्ट के लिए बेदखल किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा या किसी भी आधार पर उत्तरदायी माना जाएगा।”

धारा 16 से यह स्पष्ट है कि गैर-अस्थिरता के कारण खंड, धारा 16 के प्रावधान उस समय लागू किसी भी अन्य कानून पर प्रबल होंगे और किसी निष्क्रामित व्यक्ति की किसी भी भूमि पर कब्जे का अधिकार समाप्त नहीं किया जाएगा। तदनुसार, इस घटना में किरायेदार इसके संबंध में अधिभोग अधिकारों का आनंद ले रहे थे भूमि उनके कब्जे में है, उन्हें 2006 अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर वहां से बेदखल नहीं किया जा सकता है।

हालाँकि, धारा 16 के तहत सुरक्षा केवल निष्क्रामित संपत्ति के संबंध में ऐसे प्रभाव का निर्धारण होने के बाद ही उपलब्ध होगी। एकतरफा घोषणा स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय और प्रशासनिक निष्पक्षता के सिद्धांतों के विपरीत है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

33. जहां तक श्री शाह और श्री गुप्ता की दलीलों के दूसरे अंग का सवाल है, यह उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट कार्यवाही का विषय है, इस संबंध में हमारी ओर से कोई राय व्यक्त करना उचित नहीं होगा। उसके

34. संबंधित पक्षों की ओर से की गई दलीलों पर विचार करने के बाद, हम अपीलकर्ताओं की ओर से की गई इस दलील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं कि 2006 अधिनियम की धारा 6 के तहत 21 नवंबर, 1980 को प्रकाशित अधिसूचना, भूमि की घोषणा करती है। अपीलकर्ताओं का कब्जा निष्क्रामित संपत्ति के संरक्षक में निहित होना, अमान्य हो गया,

क्योंकि अपीलकर्ताओं को यह समझाने का अवसर देने से इनकार कर दिया गया था कि वे प्रश्न में संपत्ति के केवल रहने वाले नहीं थे, बल्कि उसके किरायेदार थे, इस मामले में, न तो प्रावधान 2008 के नियमों के नियम 9 और नियम 13-सी का इस मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

35. उपरोक्त के अलावा, रिट याचिकाकर्ताओं और राज्य के बीच जो समझौता हुआ था, वह कई कारकों पर निर्भर था, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि विचाराधीन भूमि के रहने वालों ने 37 कनाल में से 22 कनाल प्रमुख भूमि को आत्मसमर्पण कर दिया था और कस्टोडियन विभाग के पक्ष में 5 मरला जबकि 15 कनाल और 5 मरला का कब्जा शेष रहा, जिसका निपटान उनके साथ किया जाना था। जहां एक ओर, राज्य के अधिकारियों ने समझौते का फायदा उठाया और समर्पित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, वहीं बाद में राज्य सरकार की ओर से यह रुख अपनाया गया कि प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण समझौता रद्द हो गया है। 2008 नियमावली का नियम 13-सी. इस मामले की तथ्यात्मक स्थिति नियमावली 2008 के नियम 13-सी के तहत विचारित परिस्थितियों से भिन्न है। वर्तमान मामले में, निपटान के अंतर्गत आने वाली भूमि खाली नहीं थी और इसलिए, जब निपटान प्रारंभिक चरण में था, तब नियम 13-सी के दायरे में नहीं थी। यह केवल समझौते के तहत है कि रिट याचिकाकर्ताओं के दावे और अधिकार, यदि कोई हों, को

आत्मसमर्पण करना आवश्यक था और इसलिए, 37 कनाल और 5 मरला में से 22 कनाल भूमि के कब्जे के वास्तविक आत्मसमर्पण का सवाल था। पालन करें, अधिभोग अधिकारों और उसके संबंध में किरायेदारों को आवंटित करने के लिए 15 कनाल और 5 मरला का शेष भाग छोड़ दें।

36. मामले के विशेष तथ्य वर्तमान को स्थापित करते हैं नियम 13-सी के संदर्भ में रिक्त भूमि के पट्टे देने के मामलों के अलावा समझौते/निपटान को अलग तरह से माना जाना चाहिए। सबसे पहले, चूंकि भूमि खाली नहीं थी, नियम 13-सी का पहला मानदंड पूरा नहीं हुआ था और भूमि का पट्टा निपटान पैकेट के हिस्से के रूप में दिया जाना था, जिसमें 22 कनाल प्रमुख भूमि का समर्पण शामिल था। हम मंसूर अहमद मीर, जे. द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत होने के इच्छुक हैं कि इस मामले के विशेष तथ्यों में, 2008 के नियमों के नियम 13-सी का पार्टियों के बीच हुए समझौते पर कोई लागू नहीं होगा और वे नहीं थे इसलिए, उसके संबंध में दिए जाने वाले पट्टों के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम का निर्धारण करने के लिए भूमि को नीलामी में न रखना अनुचित है। जैसा कि उनके आधिपत्य द्वारा देखा गया था, यह किसी का मामला नहीं था कि समझौता किसी धोखाधड़ी का परिणाम था या गैरकानूनी था और उस पर हस्ताक्षर किए जाने और उस पर कार्रवाई किए

जाने के बाद, पार्टियों के लिए बाध्यकारी था और इसे एकतरफा वापस नहीं लिया जा सकता था।

37. हमारे विचार में, पार्टियों के बीच हुआ समझौता और 2006 के सीएमपी संख्या 128 के माध्यम से स्वीकृति के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया समझौता वैध है और संहिता के आदेश 23 के उप-नियम (3) के दायरे में है। नागरिक प्रक्रिया। निपटान को 2008 के नियमों के नियम 13-सी के प्रावधानों के विपरीत मानने का निर्णय, जैसा कि 15 सितंबर, 2007 को एच. लम्तियाज़ हुसैन, जे. द्वारा आयोजित किया गया था, और तीसरे विद्वान न्यायाधीश, वाई.पी. द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। नरगोत्रा, जे. के 25 मार्च, 2008 के फैसले और आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता और इसे रद्द कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, मंसूर अहमद मीर, जे. द्वारा व्यक्त विचार को बरकरार रखा गया है। तदनुसार, 2006 की सीएमपी संख्या 525 को खारिज किया जाता है और 2006 की सीएमपी संख्या 128 को अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय न्यायालय के बाहर समझौते को स्वीकार करने और एलपीए के साथ-साथ 2003 के ओडब्ल्यूपी नंबर 480 और ओडब्ल्यूपी नंबर 454 के संदर्भ में पार्टियों के अधिकारों के समायोजन के लिए उचित आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा। 2005.

38. चूंकि, इन अपीलों में हमें केवल इस बात पर विचार करने के लिए कहा गया है कि क्या 2008 के नियमों के नियम 13-सी के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण पार्टियों के बीच हुआ समझौता रद्द हो गया है, हमने व्यक्त नहीं किया है 2006 अधिनियम की धारा 6 की संवैधानिकता के संबंध में प्रस्तुत प्रस्तुतियों के दूसरे भाग के संबंध में कोई राय। तदनुसार, उक्त मुद्दे को निर्णय के लिए उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया गया है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस निर्णय में जो कुछ भी व्यक्त किया गया है, वह किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होगा और/या उक्त मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा।

39. तदनुसार, अपीलों का निपटारा किया जाता है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.बी.बी.

अपीलों का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी श्री आशीष जयपाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
